ont>

Title: Regarding alleged misuse of Prevention of Terrorism Act (POTA) in different parts of the country.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जब सदन में पोटा के संबंध में चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा था कि टाडा की तरह पोटा का भी दुरुपयोग होगा। जब राज्य सभा से पोटा पास नहीं हो सका, तो 26 मार्च, 2002 को सरकार ने पोटा पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया। आज देश के िवभिन्न प्रान्तों में जहां भाजपा या भाजपा समर्थित सरकारें हैं, वहां पोटा का बेतहाशा दुरुपयोग हो रहा है। अकेले झारखण्ड में 210 लोगों को पोटा में गिरफ्तार किया गया है। वहां 83 लोगों के खिलाफ पोटा सरकार को वापस लेना पडा है।'वीक' मैगजीन में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी डिटेल छपी है। जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें अधिकांश औरतें, बच्चे और आदिवासी लोग हैं - महंत कुमारी, विनोद सिंह - 12 वर्ा, जटा भूरिया, रोपुल कुमारी - 17 वर्ा, देवशरण महतो और जानकी भूरिया - 14 वर्ा । इनमें अधिकांश बच्चे हैं और महंत कुमारी तो सातवीं कक्षा की छात्रा है। कहा जा रहा है कि ये सब एमसीसी के कार्यकर्ता हैं। इसी प्रकार साप्ताहिक पत्रिका 'नक्कीरन' के सम्पादक, श्री आर.आर. गोपाल को भी गिरफ्तार किया गया है। मैं दलगत बात नहीं कहना चाहता हूं। यह भी कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि और श्री रजनीकांत को भी गिरफ्तार करेंगे। यह बहुत गम्भीर मामला है। मानवाधिकार समिति ने झारखण्ड का दौरा करने के बाद कहा है कि सरकार दिमागी तौर पर तैयार है और 3200 लोगों को पोटा के तहत गिरफ्तार किया जाना है। पोटा पास करने के समय जब वाइको साहब सदन में थे, तो बहुत जोरों से समर्थन कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद हमने कहा था कि वाइको साहब की गिरफ्तारी उचित नहीं है। तब भारत सरकार ने कहा कि वाइको के खिलाफ सबूत बनते हैं और वाइको को ठीक गिरफ्तार किया गया है। सरकार अदालत में जाकर यह कह रही है कि पहले जो पक्ष रखा था, वह सही नहीं था। सही मायनों में वाइको साहब को बचाने का काम हो रहा है। इस संबंध में भारत सरकार ने बताया है कि इसके लिए समीक्षा समिति बना दी गई है। गृह राज्य मंत्री, श्री हरिन पाठक द्वारा 28 मार्च का यह खत है। इसमें लिखा है - सरकार ने समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसके अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री अरुण बी सहाय(सेवानिवृत्त) होंगे। यह समिति विभिन्न राज्यों में पोटा, 2002 के इस्तेमाल की व्यापक जांच करेगी और अपना निर्का तथा इस कानून के कार्यान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देगी। इस बात को भी सुनिश्चित करेगी और विशेा बल देगी कि इस कानून के उपबन्ध आतंकवाद को रोकने के लिए लागू किए जायें। इसे सामान्य अपराधी या व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तेमाल न किया जाए, जो आतंकवादी नहीं हैं अथवा जिसका कार्यकलाप आतंकवादी कार्यकलाप नहीं कहा जा सकता है। पोटा बनाने का मकसद आतंकवादियों से निपटना था।

लेकिन आज राजनीतिक विद्वेा की भावना से काम किया जा रहा है। इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है। संसद पर जो हमला हुआ और जिस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हो रही है, उसने भी टिप्पणी की है कि विभिन्न राज्यों में पोटा का दुरुपयोग हो रहा है और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। कल भी यह सवाल आया था â€¦ (व्यवधान)अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगा।

अध्यक्ष महोदयः आप सब दो-दो मिनट बोल सकते हैं क्योंकि इस विाय में दूसरे लोगों के भी नोटिस हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। पोटा का अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है। इस संबंध में समीक्षा समिति क्या कर रही है? राजा भैया एंव उदय प्रताप के सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया है? हम इसमें आपका संरक्षण चाहते हैं। सरकार इस बारे में एक बयान दे और पोटा कानून रद्द हो। ...(*Interruptions*)

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Sir, yesterday you have promised that you would give me a chance today.

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Sir, I have also given a notice on this issue. ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I now give the floor to Shri Basu Deb Acharia. Each hon. Member should take only two minutes and not more than two minutes.

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, serious apprehensions were expressed by the entire Opposition, when POTA was enacted in the Joint Session of both Houses of Parliament, and also when this was discussed in this very House that this Act would be misused.

In Jharkhand, hundreds of people belonging to *Adivasi*, 90 per cent of the core agricultural labourers and even minor children have been arrested under POTA. Sir, POTA is being indiscriminately used in Jharkhand, and ordinary citizens, mostly illiterate tribals, Scheduled Castes, OBCs and minors under 18 years of age, were booked under POTA. During these two years, that is, in 2002 and 2003, more than 200 persons were booked under POTA. Even an advocate of Daltenganj (Jharkhand) was arrested because he appeared before the court in respect of some cases.

12.38 hrs. (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

There are a number of such cases in Jharkhand, Uttar Pradesh and also in Tamil Nadu. Our colleague is still under arrest and he has not been released. The Deputy Prime Minister, who is also the Home Minister, made a statement on the floor of this House that POTA cases would be reviewed and some safeguards would be provided so that POTA would not be misused. We do not know whether any review has taken place or not. Even a journalist in Tamil Nadu has been booked under POTA. Journalists, advocates, agricultural labourers and even minor children below the age of 18 are being arrested, and POTA is blatantly being misused by a number of State Governments.

We were told that such a law was required to tackle the problem of terrorism. However, this Act has not helped in reducing terrorism. This law has failed in achieving its intended purpose. Time has come now to review, not only review but also to withdraw, such a draconian Act which is being blatantly misused for political ends by certain State Governments.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, POTA has been proved to be a draconian law. In spite of the strong opposition put up by the Opposition parties in both the Houses of Parliament to the passage of this legislation, this legislation was passed by calling a Joint Session of Parliament. An assurance was given in this House during the discussion that this legislation would not be misused. It was an assurance given by the Home Minister and even by the Prime Minister himself. What is happening nowadays? It is used against hon. Member Vaiko. It is not only being misused but it is being used against political opponents of the Ruling Party in certain States. The time has come to repeal this draconian law. I urge that this Act be repealed forthwith.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में...â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास पोटा के बारे में 4-5 सदस्यों का नोटिस आया है, उन्हें चांस दूंगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष जी, जब इस सदन में पोटा के बारे में कानून आया, हमने बार बार इसकी खिलाफत की लेकिन सरकार ने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। आज धड़ल्ले से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। इस कानून के तहत बेकसूर, निर्दोा लोगों को पकड़ा जा रहा है और बदले की भावना से किया जा रहा है। उदाहरण के लिये तमिलनाडु में श्री वैको की गिरफ्तारी की गई। शुरु में केन्द्र सरकार ने कहा कि यह ठीक है लेकिन बाद में हलफनामा देकर यह बताया कि पोटा के खिलाफ कानून लाया जायेगा। केन्द्र सरकार का दोहरा मापदंड कैसे हैं? इस कानून का प्रयोग राजनैतिक भावना और बदले के लिये हो रहा है। राज्य सरकारें इस कानून के तहत दुरुपयोग कर रही हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अटार्नी जनरल को नोटिस जारी किया है कि पोटा की असलियत क्या है, इसमें जमानत का क्या प्रावधान है। इन सब बातों का पर्दाफाश कोर्ट में हुआ है। मेरी मांग है कि सरकार इस पर वक्तव्य दे और पोटा कानून को वापस करना चाहिये।

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, when this draconian law POTA was brought before the House by the Government, during the discussion the entire Opposition raised strong objections to its adoption. We apprehended that this law would be misused and used against the political opponents, journalists and innocent people. ...(*Interruptions*)

We have the reasonable doubts. Our apprehension was correct. Though the hon. Home Minister assured us on the floor of the House that this law would not be misused, but in some States including Jharkhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Gujarat, this law is being misused. In Jharkhand alone, more than 100 people including several minor boys were arrested under POTA.

Day before yesterday, the situation of Uttar Pradesh was being discussed in the House. We all know how at the behest of the Chief Minister of Uttar Pradesh, the Government of Uttar Pradesh initiated the cases against our hon. senior colleague Shri Mulayam Singh Yadav. They are preparing the grounds. The Government of Uttar Pradesh wants to book our hon. colleague Shri Mulayam Singh Yadav under POTA.

Similarly, the Government of Tamil Nadu also arrested our hon. senior colleague Shri Vaiko for a long period. Though his party and he supported POTA, yet in spite of the differences with Shri Vaiko, we cannot support the arrest of Shri Vaiko under the draconian law POTA.

MR DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajoy Chakraborty, please do not make a speech. Kindly conclude.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I am just concluding.

Sir, we are observing that this law is being misused. So, this law should be repealed. I urge upon the Government of India that in the interest of the people of this country, this law should be repealed. The Government should withdraw this draconian law immediately and forthwith.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Priya Ranjan Dasmunsi.

...(*Interruptions*)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Mr. Deputy-Speaker, Sir, from the Congress party and the rest of the Opposition, from day one this Bill was opposed...(*Interruptions*)

श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर (वडोदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही सब्जैक्ट पर बहस हो रही है, मैं अपनी स्टेट का महत्वपूर्ण विाय उठाना चाहती हूं।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, these people have given notices.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Madam, it is on Adjournment Motion....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Speaker has already discussed with them.

SHRIMATI JAYABEN B. THAKKAR : Sir, ours is also a very important matter relating to our State. We should also be permitted to raise our issue....(*Interruptions*) This is not fair. Only one subject is being

discussed....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everybody will get a chance, provided you all cooperate.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the Congress party from day one has been objecting POTA. Our Chief Ministers did not use this Act as the Government desired.

Sir, misuse of POTA in Gujarat, Jharkhand, Tamil Nadu and Uttar Pradesh has opened the eyes of many people in the country including the top persons in the Judiciary. Now, the Home Ministry has considered to have a Review Commission. Why is there a Review Commission? It is because now they feel that that monster may hit them back. That is why they are afraid.

Sir, I wrote a letter to the hon. Deputy Prime Minister quoting the specific provisions of POTA, citing the speeches of Shri Ashok Singhal, Shri Praveen Togadia and Shri Giriraj Kishore. And, the Home Minister did not feel it important even to acknowledge my letter because he has no way to answer it as he is caught in his own nightmare.

Now, Mr. Deputy-Speaker, Sir, when the Government felt that the monster may hit them back, they tried to control their allies saying that they are making a review of it. Yesterday, on the observation of the Supreme Court, on the very condition of the bail and other provisions, the Government is now in the dark.

I, therefore, feel that to get rid of the total embarrassment, they should look at our Chief Minister in Jammu and Kashmir, Shri Mufti Mohammad Sayeed as to how he is trying to handle the atmosphere in a manner, which a leader of the House should do.

Therefore, a time has come for the Government to outrightly scrap it, and bring a Repeal Bill. Unanimous recommendations of the House will be there.

Sir, I am afraid that in Uttar Pradesh and in many other States, this particular Act will be used. As the elections for Assembly and Parliament approach, the Ruling party will not spare even its own allies! Please do not be under any misunderstanding.

Shri Raghunath Jha is nodding his head. I am thankful to you, Shri Jha.

यह आप लोगों के लिए भी होगा। इसलिए तुरंत आवाज उठाइये, इसे रिपील करो और इसे खत्म करो।â€¦ (व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : दासमुंशी जी, आप कितना ही बहकाने की कोशिश करें, ये लोग टूटने वाले नहीं है। यह सरकार लगातार चल रही है और पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not shout like this.

...(*Interruptions*)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप लोगों के लिए चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन हमने पोटा में नहीं किया। तोगड़िया के लिए इंडियन पीनल कोड काफी है। आप बिहार जाइये वहां लालू जी 30 तारीख को लाठी रैली कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ज़ीरो आवर है, आप केवल असोसियेट कीजिएगा।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे ज़िले का मामला है। प्रतापगढ़ में राजा उदय प्रताप सिंह जो 70 वर्ा के हो चुके हैं, वे विश्व हिन्दू परिष ाद् के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं और जो इनकी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मेरे दल के नहीं हैं, उन 70 साल के उदय प्रताप सिंह को पोटा के तहत गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जा रहा है जो। वे पांच साल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मेरे जिले के हैं। उनको कानपुर में तनहाई में रखा गया है। गोपालजी एम.एल.सी. हैं. उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है। इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने दूसरा नोटिस भी ज़ीरो आवर के लिए दिया है। â€¦ (व्यवधान)प्रतापगढ़ में मेरे जिले में सियाराम यादव जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, विवेक त्रिपाठी, युवजन सभा के अध्यक्ष तथा महिला सभा की अध्यक्षा रेहाना सिद्दीकी, सब पर पोटा लगाने की कोशिश की जा रही है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The subject is different. This is a different subject. You are deviating from the subject.

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मैंने इस पर नोटिस दिया है। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले एक विाय खत्म करना है, फिर दूसरा विाय लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उन् सब लोगों को अकारण घर से उठाकर बंद कर दिया है। इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार को तत्काल इस पर िवचार करना चाहिए और मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूँ कि यह एक विवेकहीन कदम है। इससे देश को नुकसान होगा और देश में जो तानाशाह लोग बैठे हैं, वे उस कानून का दुरुपयोग करेंगे। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Many hon. Members are there to make submissions. How will they get their chances?

श्री चन्द्रनाथ सिंह : इसलिए पोटा पर तत्काल डिसकशन होना चाहिए और उस पर विचार करने के बाद उसको समाप्त करना चाहिए। पहले भी मैंने अनुरोध किया था और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यही मुसीबत है आप लोगों की, कि आप भााण करना शुरू कर देते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI RUPCHAND PAL (HOOGLY): Our apprehension at that time when it was being pushed through was − we expressed our apprehension − that that would be misused. Now, we find that not only in Tamil Nadu where it is being applied to Mr. Vaiko, but also in U.P., and in Jharkhand, it is being used against minors, against women, against aged, and against others, sometimes for personal scores and some other times for political scores. If there is an offence committed, there is no dearth of criminal law. But we do find that POTA is being used in such situations. The least that should be done immediately and forthwith is that it should be repealed so that it is not used against any other political opponent in the country. â€¦ (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, may I draw your attention? â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, आपको भी मौका मिलेगा। अभी पोटा पर बात चल रही है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I will finish in one minute.

उपाध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, आपका नोटिस जम्मू और कश्मीर में किलिंग्ज़ पर है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : पोटा पर भी है। वह हिन्दी में लिखा हुआ है। â€¦ (व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : उधर के लोग ही सारा समय हाउस चलाते हैं, हम कहां जाएं? â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not cast aspersions like this. इन सब माननीय सदस्यों ने एक ही विाय पर नोटिस दिया है, उसी पर ये बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जाधव जी, जब पोटा पर चर्चा शुरू की है तो क्या खत्म नहीं करेंगे?

...(व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : So far as the question of misuse of POTA is concerned, the Government itself has given recognition to this serious issue because they have appointed a Committee on this. For what purpose? If there was no case at all, why should they appoint a Committee? ...(*Interruptions*) What is happening? I would like to know from the Government whether the composition of the Committee has been completed. We are only given the name of the Chairman. We do not know, till today, the other members of the Committee. May I know whether it is a one-member Committee? May I also know whether that has started its work?

Why should we argue that there is a misuse? The Government has admitted that there is a misuse. There are two telltale instances − one is the different stand of the Government with regard to Mr. Vaiko, where they just oppose and support the case of misuse.

They have supported the charge of misuse. That is why, they have formally altered the affidavit before the highest court of this land. Secondly, when the matter is being considered, on one side the Attorney General of India has filed an affidavit saying that it is a misuse and at the same time he is solemnly arguing - the same lawyer is arguing - that there is no scope for misuse under POTA. We would like to know the stand of the Government of India. Can the Government treat the human civil liberty, in this country, as a matter of just its sweet will?

This poison has now spread because it is being enforced by some Chief Ministers. These Chief Ministers are liberally misusing it. In Shri Vaiko's case, there is an admission by the Government of India that the Tamil Nadu Government has misused it and there are other cases also....(*Interruptions*) Today, we are given lectures by the same Chief Minister about parliamentary democracy. It is a joke of the century.â€¦ (*Interruptions*) Detention of Shri Vaiko was unjustified, is the case of the Government of India. It is the case of the Government of India that Shri Vaiko's detention is not proper. In spite of that...(*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): He has challenged it before the Supreme Court and even today the Supreme Court is hearing the case....(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : We are not prepared to listen lectures about the parliamentary democracy from

Chief Ministers like them. We know how they are using parliamentary democracy. Therefore, I demandâ€¦ (*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, they have been talking about POTA but nobody talked about TADA detention....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please confine to POTA only.

...(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : I demand that the Government of India should make its stand clear on it....(*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, about 400 police officials have been detained in jail for the last eight years in Punjab. Did the Members raise those issues?...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pandian, this is 'Zero Hour'. The hon. Member has raised a point.

...(*Interruptions*)

SHRI P.H. PANDIAN : Sir, about 400 police officials are languishing in jail in Punjab. Nobody talked about them....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have called Shri Raghunath Jha.